International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 8, Issue 12, December - 2018,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

भारतीय लोकतंत्र के नए आयाम

डॉ. केशरी नन्दन मिश्रा
एसोसिएट प्रोफेसर (इतिहास)
हेमवती नन्दन बहुगुणा राजकीय पी.जी. कालेज, नैनी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत।

स्वतंत्रता के बाद से भारत के राज्य निर्माण की कहानी में संघीय राज्यों के हिस्से पर बढ़ते प्रभाव की कहानी शामिल है। 1947 में स्वतंत्रता के समय, भारत को 1935 में ब्रिटिश-ब्रोकेड संविधान मिला था। इसने दो संभावनाओं को मूर्त रूप दिया, एक केंद्रीकृत सत्तावादी "उप-रीगल" राज्य और एक विकेन्द्रीकृत, या संघीय, संसदीय राज्य। पाकिस्तान के "महान नेता" मोहम्मद अली जिन्ना ने ब्रिटिश राज के अंतिम वायसराय और गवर्नर-जनरल, लॉर्ड लुईस माउंटबेटन के उत्तराधिकारी के रूप में अभिनय करते हुए, पूर्व विकल्प को चुना। जवाहरलाल नेहरू ने केंद्रीकृत युक्तिकरण के लिए अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण के बावजूद, बाद के पाठ्यक्रम का चयन किया और एक संघीय प्रणाली में संसदीय सरकार के प्रधान मंत्री बने। प्रस्तुत पत्र भारतीय लोकतंत्र के नए आयामों को छोड़कर, जनसंख्या और टिकाऊ और स्थायी सामुदायिक संपत्ति बनाने में उसके प्रदर्शन का आकलन करने का प्रयास करता है।

नेहरू-गांधी युग की प्रमुख-पार्टी प्रणाली, जिसके कारण 1989 में नौवें संसदीय चुनाव के बाद क्षेत्रीय बहुपक्षीय प्रणाली और गठबंधन सरकारों द्वारा कांग्रेस की बहुमत की सरकारें बनाई गईं। 1989 के चुनावों के परिणामस्वरूप भारत की पहली त्रिशंकु संसद बनी। वी.पी. सिंह की जनता पार्टी, जिसने 545 सदस्यीय लोकसभा में सीटों का सबसे बड़ा हिस्सा रखा, भारत की पहली गठबंधन सरकार का केंद्र बन गया। यह स्पष्ट है कि क्षेत्र-अनुकूल बहुदलीय प्रणाली पर आधारित गठबंधन सरकार एक मिश्रित आशीर्वाद है। इसने देश की क्षमता को अंतर के साथ और केन्द्रित राजनीति का समर्थन करने की सुविधा देकर जातीय सफाई, गृहयुद्ध और चरमपंथी राजनीति से बचना संभव बना दिया है। हालांकि, गठबंधन सरकार ने आर्थिक उदारीकरण को आगे बढ़ाने या जोरदार आर्थिक विकास हासिल करने की देश की क्षमता को कमजोर कर दिया है। पार्टी प्रणाली के परिवर्तन और गठबंधन सरकार के उदय ने राष्ट्रपति के लिए नियामक भूमिका निभाने का रास्ता भी खोल दिया है। कांग्रेस पार्टी की प्रमुखताओं के युग में, अध्यक्षों को कांग्रेस के नेता को सरकार बनाने के लिए कहने के समर्थक फॉर्म ड्यूटी से परे कुछ नहीं करना था। 1989 के बाद से, हालांकि, सरकारों के मेकअप को निर्धारित करने में राष्ट्रपति विवेक की कवायद महत्वपूर्ण हो गई है। बदले में राष्ट्रपतियों ने इस नए प्रभाव को अपने कार्यालय के लिए एक बड़ी नियामक भूमिका में बदल दिया है।

विकासशील देशों के विश्लेषक अक्सर राजनीतिक स्थिरता और वैधता के लिए आर्थिक विकास के महत्व पर जोर देते

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 8, Issue 12, December - 2018,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at:
Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

हैं। वे जो अक्सर कम नोटिस करते हैं वह योगदान है जो सामाजिक गतिशीलता राजनीतिक स्थिरता और वैधता के लिए कर सकती है। स्थिति और साथ ही दोनों के लिए आय का मामला। भारत में, एक बार संशोधित निचली जातियों के सदस्यों द्वारा प्राप्त "स्थिति वृद्धि" तेजी से बढ़ी है, और यह आर्थिक विकास की अपेक्षाकृत धीमी गति के साथ बहुत असंतोष प्रकट करता है।

लोकतंत्र, मीडिया और जनता क्षेत्र

यह पहले ही चर्चा है कि मीडिया को लोकतंत्र में चौथी संपत्ति माना गया है। लोकतंत्र, वैकल्पिक विचारों को बहस करने और समाज की भलाई के लिए निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए जगह प्रदान करता है। सार्वजनिक रूप से सहमत मानदंडों को आर्थिक संगठनों और राजनीतिक संस्थानों (बार्नेट, 2004) की ओर से किए गए कार्यों से अधिक तौला जाता है। यह सार्वजनिक क्षेत्र की अवधारणा के सार में करीब है जहां तर्कसंगत सार्वजनिक बहस और प्रवचन को महत्व दिया जाता है। व्यक्ति सामान्य चिंता के मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से चर्चा कर सकते हैं (टेस्केरिस, 2008)। सार्वजनिक क्षेत्र के गठन (पणिक्कर, 2004) के पीछे मीडिया महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक है।

मीडिया और भारतीय लोकतंत्र

भारत में सार्वजनिक सेवा प्रसारण को स्वतंत्रता के बाद बहुत महत्व दिया गया था। इसका उपयोग सामाजिक परिवर्तन के एक हथियार के रूप में किया गया था। आकाशवाणी (ऑल इंडिया रेडियो) और दूरदर्शन, देश में सार्वजनिक सेवा प्रसारकों के पास सूचना और मनोरंजन के अलावा शैक्षिक कार्यक्रम प्रदान करने की जिम्मेदारी थी। हालाँकि, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि देश में सार्वजनिक सेवा प्रसारण प्रणाली को राज्य के साथ निकटता से पहचाना गया था। राज्य के नियंत्रण में एक एकाधिकारवादी मीडिया संरचना में सत्ताधारी कुलीनों के मुखपत्र बनने का खतरा है। परिदृश्य वैश्विक प्रणाली के साथ एकीकृत करने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के उद्घाटन के साथ बदलने के लिए बाध्य था। इसने सार्वजनिक सेवा प्रसारकों के साथ मीडिया के क्षेत्र में एक प्रतिस्पर्धी बाजार के उभरने का संकेत दिया, जिसमें निजी संस्थाओं से चुनौतियां थीं। यह, हालांकि, स्वामित्व की एक नई समस्या का बीज था।

लोकतंत्र और आर्थिक विकास

यह अक्सर दावा किया जाता है कि आर्थिक विकास लाने के लिए गैर-लोकतांत्रिक प्रणाली बेहतर है। यह विश्वास कभी-कभी सिंगापुर के नेता और पूर्व राष्ट्रपति ली कुआन यू की वकालत के कारण "ली परिकल्पना" के नाम से जाता है। वह निश्चित रूप से सही है कि कुछ अनुशासनात्मक राज्यों (जैसे कि दक्षिण कोरिया, उसका अपना सिंगापुर और पोस्टरेफॉर्म चीन) में कई कम आधिकारिक लोगों (भारत, जमैका और कोस्टा रिका सहित) की तुलना में आर्थिक विकास की दर तेज है। "ली परिकल्पना", हालांकि, छिटपुट अनुभववाद पर आधारित है, जो कि व्यापक रूप से उपलब्ध डेटा पर किसी भी सामान्य सांख्यिकीय परीक्षण के बजाय बहुत ही चयनात्मक और सीमित जानकारी पर

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 8, Issue 12, December - 2018,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at:
Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

आधारित है। इस तरह का एक सामान्य संबंध बहुत चुनिंदा साक्ष्यों के आधार पर स्थापित नहीं किया जा सकता है।

भारत में लोकतांत्रिक एकीकरण

भारत में बहुलतावादी लोकतंत्र का विकास आंतरिक और बाहरी शक्तियों की एक विस्तृत श्रृंखला के रूप में हुआ है। एक संख्या स्पष्ट रूप से पहचानी जा सकती है। पहला, भारत का उदार लोकतंत्र ब्रिटिश शासन से पहले के राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था पर भारी पड़ता है। जाति, धर्म और जनजाति के संबंधों ने श्रम और सामाजिक पदानुक्रम का एक अनौपचारिक विभाजन प्रदान किया-और इसलिए 24 ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से पहले कई शताब्दियों तक प्रतिबंधों और विनियमों की एक अनियोजित प्रणाली थी। पूर्व-औपनिवेशिक भारत में सामाजिक स्थिरता में इनका योगदान था। उन्होंने राजनीतिक गोलबंदी के लिए आधार भी प्रदान किए जो स्वतंत्रता के बाद समाप्त हो गए हैं। इसके अलावा, मुगल शासन के तहत जगह में राजनीतिक और प्रशासनिक प्रणाली को व्यापक रूप से अंग्रेजों द्वारा बनाए रखा गया था। भारत के एक तिहाई क्षेत्र, राजनैतिक और तार्किक कारणों से, आजादी तक रियासत के अधीन रहे।

लोकतंत्र और सामाजिक अधिकार

शायद भारत में पोषण की स्थिति का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि वस्तुतः इसकी कोई चर्चा नहीं है, विशेष मंडलियों के बाहर। सार्वजनिक बहसों और चुनावी राजनीति में पुरानी भूख शायद ही कभी दिखती है। समझाने के लिए, मुख्यधारा के मीडिया में पोषण के मुद्दों की कवरेज पर विचार करें। बेहतरीन अंग्रेजी-माध्यम के दैनिकों में से एक, हिंदू अपने संपादकीय पृष्ठ पर हर दिन दो राय लेख प्रकाशित करता है। छह महीने (जनवरी से जून 2000) की अवधि में इन राय लेखों की हाल की गणना में, यह पाया गया कि स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, गरीबी, लिंग, मानव अधिकार और संबंधित सामाजिक मुद्दों को मिलाकर 300 लेखों में से बमुश्किल 30 के लिए जिम्मेदार है । इन 300 लेखों में, कोई भी स्वास्थ्य या पोषण से नहीं निपटता है। 12 जैसा कि यह सरल अभ्यास दिखाता है, भारतीय लोगों की बुनियादी जरूरतें सार्वजनिक बहसों और लोकतांत्रिक राजनीति में बहुत कम हैं, और पोषण संबंधी मुद्दे विशेष रूप से ध्यान से बाहर हैं।

निष्कर्ष

देश में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों के लिए एक आशीर्वाद है। हालाँकि, यह आशीर्वाद बहुत गलत हो सकता है जब इसमें हेरफेर सेट किया जाता है। मीडिया संगठनों में स्व विनियामक तंत्र को विसंगतियों को रोकने के लिए पर्याप्त मजबूत होना चाहिए जब भी वे होते हैं। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जैसी एजेंसियों को सड़ने से बचने के लिए सतर्क रहने की जरूरत है। बड़े मीडिया समूह एक गंभीर खतरा हैं। इस समस्या का सामना करने के लिए बहुलवादी मीडिया संगठनों को जो आर्थिक रूप से व्यवहार्य हैं, उन्हें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। सामुदायिक भागीदारी एक लक्ष्य है जिसे मीडिया को भारत जैसे देश में प्रयास करना चाहिए।

References

1. Flew T. Democracy, participation and convergent media: case studies in contemporary online news journalism in Australia. Communication, Politics & Culture. 2009; 42(2):87-115.
2. Habermas J. Information and democracy. In F. Webster (Ed.), Theories of the Information Society. New York, NY: Taylor & Francis, 2006, 161-163.
3. Jebaraj P. Opinion: The spotlight is on the media now. The Hindu, 2010. Retrieved from http://www.thehindu.com/opinion/lead/article907823.ece
4. Refer to World Bank, Sub-Saharan Africa.
5. Leftwich. Governance, democracy and development in the Third World, 609.
6. Lancaster. Governance and development, 10.
7. Thompson, Late industrialisers, late democratisers